संचार निदेशक, रांची के विरुद्ध सी०बी० आई० की जांच

1430. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ए०के० सिन्हा, संचार निदेशक, रांची को जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठा की पदवी दिलायी गई, उस समय उनके विरुद्ध सी०बी० आई० की जांच चल रही थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने एक या दो व्यक्तियों को एस०टी०डी० के साथ सैकड़ों टेलीफोन बूथ आबंटित किये हैं और उसके एवज में भारी कमीशन लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जब श्री ए०के० सिन्हा बतौर निदेशक दूरसंचार डिब्रूगढ़ में तैनात किए गए थे और वे 25-8-1982 से 4-1-1990 की अवधि में वहां कार्य कर रहे थे तब उनके विरुद्ध जांच-पड़ताल संबंधी सी०बी०आई० के दो मामले दर्ज किए थे। एक मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके नियमित विभागीय कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। दूसरा मामला सी०बी० आई० द्वारा बन्द कर दिया गया है। श्री सिन्हा को कोई सरकारी पुरस्कार नहीं दिया गया है। परन्तु, ऐसा पता चला है कि एक स्वयंसेवी संगठन, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसायटी आफ इंडिया द्वारा उन्हें असम तथा उत्तर-पूर्वी सर्किलों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए "विजय रत्न" पुरस्कार प्रदान किया गया था।

(ख) जनवरी, 1990 से जून, 1991 तक के दौरान केवल 19 निजी पे-फोन खोले गए थे। मुख्य महाप्रबन्धक बिहार दूरसंचार सर्किल द्वारा इन मंजूरियों में किसी प्रकार की कोई अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Cellular Telephones

1431. **SHRI RAMDAS AGARWAL:** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "India set to import Cellular Telephones" published in the Hindustan Times dated 7th July, 1991;

(b) if so, what are the reasons for revival of above mentioned proposal when the previous Chairman of the Telecom. Commission had shown his unwillingness and opposed import of car telephones in the country;

(c) whether the present deal, apart from U.S. firm "Motorola", Government held negotiations with other leading and equally reputed firms in the system, if not, what are the reasons therefor; and

(d) what is the total amount of foreign exchange now involved when the country is in dire need of foreign exchange, indicating initially imported equipment and proposed allocation of such telephone lines in different cities in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Yes Sir. Although the Department is working on a scheme in con-

sultation with Ministry of Finance to provide this facility to registrants at a high premium in foreign exchange in such a manner that the premium not only finances the cost of equipments but also generates surplus revenue for provision of public telephones in resettlement colonies, Jhuggi Jhonri Clusters, low income group housing societies, there is no proposal at present to import Cellular telephones.

(c) Against the Tender Enquiry of M/s. Motorola, C-DOT had submitted a bid in competition with other international firms for development of Cellular Application Plat form (CAP). Only a letter of intent has been signed last month between M/s. Motorola and C-DOT to enter into a contractual relationship that will enable Motorola Cellular Systems to work C-DOT switches through appropriate interfaces.

(d) No foreign exchange is involved in the above proposal.

8वीं योजना के दौरान दूर-संचार के आधुनिकीकरण पर व्यय

1432. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण तथा आवश्यक अत्याधुनिक उपस्करों के आयात पर कितना खर्चा आयेगा, क्या इस संबंध में विश्वभर में निविदायें आमंत्रित की गयी हैं ;

(ख) आठवीं योजना के दौरान दूरसंचार विभाग, डाक विभाग तथा तार विभाग के विस्तार, विकास तथा आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(ग) केन्द्रीय स्तर से क्षेत्रीय (राज्य) स्तर के उन ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है जो एक करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के उपकरण सप्लाई करेंगे;

(घ) उन भारतीय तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जो 5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक के तथा 15 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के उपकरण सप्लाई करेंगे तथा उन्हें आवंटित किये गये काम/आवंटित किए जाने वाले प्रस्तावित काम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आठवीं योजना के दौरान इस मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मसौदे में 19700 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में 212 करोड़ रुपये की राशि दूरसंचार उपस्करों के आयात के लिए निर्धारित की गई है। सामान्य अभिप्राय, बहुत थोड़ी कमियों के लिए छोड़कर, तैयार उपस्कर आयात न करने का है। इस कार्य पर दूरसंचार उपकरणों के लिए विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई है।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मसौदे के अनुसार तार सुविधाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण के लिए 19700 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है. डाक विभाग के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में डाक सेवाओं के विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण के लिए 205 करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र से क्षेत्रीय (राज्य) स्तर तक ठेकेदारों के ब्यौरे तैयार नहीं किये जा सकते क्योंकि आपूर्ति खुली व्यावसायिक निविदाओं द्वारा की जाती है और ठेकेदारों के ब्यौरे भिन्न-भिन्न, निविदाओं में भिन्न-भिन्न हैं। अधिकांश आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मै० आई०टी०आई० मै० एच०सी०एल०, मै० बी०ई०एल० आदि द्वारा की जाती है।